



SATYADHEESH

सत्याधीश

यूपीएससी दैनिक विस्तृत नोट्स

करेंट अफेयर्स • 7 सितंबर 2026

22 नोट्स	1 खबरें जोड़ी गईं	GS2 • 9 पेपर मिश्रण	GS3 • 13
-------------	----------------------	------------------------	----------

विषय सूची

सभी नोट्स, पेपर के अनुसार

GS2	राज्यव्यवस्था • शासन • सामाजिक न्याय • अंतर्राष्ट्रीय संबंध	9 नोट्स
	राज्यव्यवस्था एवं संविधान	3
	शासन	1
	सामाजिक न्याय	2
	अंतर्राष्ट्रीय संबंध	3
GS3	अर्थव्यवस्था • विज्ञान-तकनीक • पर्यावरण • सुरक्षा	13 नोट्स
	अर्थव्यवस्था	8
	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी	5

हर नोट में

चर्चा में क्यों → याद रखने योग्य तथ्य → कीवर्ड के साथ मेन्स प्रश्न। एक ही खबर की रिपोर्टें जोड़ दी गई हैं।

समय कम है?

5 पेज के सार में सबसे ज़रूरी खबरें और अभ्यास प्रश्न हैं।

राज्यवस्था एवं संविधान

3

JUDICIARY & LANDMARK JUDGMENTS

P

M

2 रिपोर्टें जोड़ी गईं

7 सितंबर • The Hindu • satyadheesh.in/news/118733

दिल्ली के सत्य निकेतन में बिल्डिंग गिरी, 7 छात्रों की मौत

चर्चा में क्यों सत्य निकेतन में एक इमारत ढहने से सात छात्रों की मृत्यु होने के उपरान्त, दिल्ली उच्च न्यायालय (Delhi High Court) ने नगर निगम दिल्ली (MCD) को PG छात्रावासों का निरीक्षण करने का निर्देश दिया है।

तथ्य	सत्य निकेतन भवन ढहने से सात छात्रों की मृत्यु हो गई और कई अन्य घायल हो गए।
पद	बिना लाइसेंस के PG चलाने के लिए हरिराम गुप्ता (82), उर्मिला गुप्ता (75) और महेश गुप्ता (52) को गिरफ्तार किया गया।
स्थान	सत्य निकेतन दिल्ली का एक स्थानीय क्षेत्र है जो छात्र आवास के लिए जाना जाता है।

मेन्स प्रश्न शहरी केंद्रों में निजी पीजी (PG) आवासों के प्रबंधन में आने वाली विनियामक चुनौतियों का विश्लेषण कीजिए और संरचनात्मक सुरक्षा एवं छात्र कल्याण सुनिश्चित करने के लिए उचित उपायों का सुझाव दीजिए।

ELECTIONS, ECI & ELECTORAL REFORMS

P

7 सितंबर • The Hindu • satyadheesh.in/news/118581

मणिपुर में 1,32,456 वोटर्स के नाम वोटर लिस्ट से हटाए गए

चर्चा में क्यों भारत निर्वाचन आयोग (ECI) ने विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) अभ्यास के पश्चात मणिपुर और सिक्किम के लिए अंतिम फोटोयुक्त मतदाता सूची प्रकाशित की है, जिससे मतदाता सूची से नाम हटाए जाने के संबंध में कुकी-जो समूहों की चिंताएं उत्पन्न हुई हैं।

तथ्य	मणिपुर की अंतिम निर्वाचक नामा गणना: 19,60,620।
तथ्य	सिक्किम की अंतिम मतदाता सूची संख्या: 4,18,467।
संस्था	विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) भारत निर्वाचन आयोग द्वारा आयोजित एक अभ्यास है।
तथ्य	मणिपुर में मतदाता विलोपन: 1,32,456।
तथ्य	सिक्किम मतदाता विलोपन: 52,614।

मेन्स प्रश्न आंतरिक विस्थापन और जातीय संघर्ष का सामना कर रहे क्षेत्रों में समावेशी मतदाता सूची बनाए रखने में आने वाली चुनौतियों का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए।

JUDICIARY & LANDMARK JUDGMENTS

P

7 सितंबर • NDTV • satyadheesh.in/news/118471

लद्दाख में जम्मू-कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट की बेंच शुरू

चर्चा में क्यों दूरस्थ क्षेत्रों में न्यायिक सुलभता में सुधार हेतु जम्मू और कश्मीर तथा लद्दाख उच्च न्यायालय को लद्दाख में बैठने की अनुमति देने वाला विनियमन 5 सितंबर, 2026 से प्रभावी हो गया है।

स्थान	जम्मू और कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय: इसके क्षेत्राधिकार में लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश शामिल है।
तथ्य	विनियमन प्रभावी तिथि: 5 सितंबर, 2026।
पद	लद्दाख के उपराज्यपाल: VK Saxena।

मेन्स प्रश्न दूरस्थ आबादी तक न्याय की प्रभावी पहुंच सुनिश्चित करने के लिए केंद्र शासित प्रदेशों में क्षेत्रीय न्यायिक पीठों की स्थापना के महत्व पर चर्चा कीजिए।

महाराष्ट्र में भर्ती परीक्षाओं में सुधार के लिए 7 सदस्यीय पैनल गठित

चर्चा में क्यों महाराष्ट्र सामान्य प्रशासन विभाग ने राज्य सरकार की भर्ती परीक्षाओं में पारदर्शिता और निष्पक्षता बढ़ाने हेतु सुधारों की समीक्षा और सुझाव देने के लिए वी. राधा की अध्यक्षता में एक सात सदस्यीय समिति का गठन किया है।

संस्था	सामान्य प्रशासन विभाग: महाराष्ट्र में भर्ती सुधार समिति के गठन के लिए जिम्मेदार राज्य निकाय।
पद	वी. राधा: अतिरिक्त मुख्य सचिव (सेवाएं) और भर्ती सुधार समिति की अध्यक्ष।
तथ्य	समिति में IIT Mumbai के एक प्रोफेसर सहित सात सदस्य शामिल हैं।

मेन्स प्रश्न भारत में राज्य सिविल सेवाओं की भर्ती प्रक्रियाओं में पारदर्शिता और सत्यनिष्ठा सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक उपायों की चर्चा कीजिए।

सामाजिक न्याय

मेडिकल एग्जाम पेपर लीक से 2 मिलियन छात्र दोबारा देंगे टेस्ट, मंत्री ने इस्तीफा दिया

चर्चा में क्यों जून 2024 में एक चिकित्सा प्रवेश परीक्षा प्रश्नपत्र लीक होने के कारण दो मिलियन से अधिक छात्रों को परीक्षा पुनः देनी पड़ी, जिसके परिणामस्वरूप केंद्रीय शिक्षा मंत्री को इस्तीफा देना पड़ा।

संस्था	National Testing Agency (NTA): निष्पक्ष और मानकीकृत परीक्षा आयोजित करने के लिए 2017 में स्थापित।
तथ्य	जून 2024 में पेपर लीक के कारण दो मिलियन से अधिक छात्रों को मेडिकल प्रवेश परीक्षा पुनः देनी पड़ी।
पद	नंदन निलेकणी: परीक्षा संचालन के लिए सुधारों की सिफारिश करने हेतु एक उच्च-स्तरीय टास्क फोर्स का नेतृत्व करने के लिए नियुक्त।

मेन्स प्रश्न भारत में बड़े पैमाने पर आयोजित होने वाली प्रवेश परीक्षाओं में मौजूद प्रणालीगत कमजोरियों का विश्लेषण कीजिए और परीक्षा प्रक्रिया की शुचिता सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक उपायों का सुझाव दीजिए। चर्चा कीजिए।

भारत में कैश ट्रांसफर स्कीम पर खर्च होंगे 18 बिलियन डॉलर

चर्चा में क्यों राज्य सरकारें घरेलू कार्यों के अवैतनिक श्रम को मान्यता देने और SDG 5.4 को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से वर्ष 2025-26 में 'अनकंडीशनल कैश ट्रांसफर' (UCT) योजनाओं पर 18 बिलियन डॉलर खर्च करने का अनुमान है।

तथ्य	भारत में 2025-26 के लिए UCT योजनाओं पर अनुमानित व्यय \$18 बिलियन है।
तथ्य	भारत में UCT योजनाएं 2020 से सक्रिय हैं।
तथ्य	SDG 5.4 अवैतनिक देखभाल और घरेलू कार्य को पहचानने और उन्हें महत्व देने से संबंधित है।
स्थान	Kalaigarn Magalir Urimai Thittam, Lakshmi Bhandar, और Gruha Lakshmi Yojana भारतीय राज्यों में कार्यान्वित विशिष्ट UCT योजनाएं हैं।

मेन्स प्रश्न भारत में महिलाओं के सामाजिक-आर्थिक सशक्तिकरण और सतत विकास लक्ष्यों (SDGs) की प्राप्ति में 'बिना शर्त नकद हस्तांतरण' (Unconditional Cash Transfer) योजनाओं के योगदान का विश्लेषण कीजिए।

INTERNATIONAL INSTITUTIONS & AGENCIES (UN, WTO, IMF...) M

7 सितंबर · Al Jazeera · satyadheesh.in/news/118736

गाज़ा में नरसंहार का 'संभावित खतरा', इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की चेतावनी

चर्चा में क्यों इज़राइल द्वारा लगाए गए नाकेबंदी और बुनियादी ढांचे के विनाश के आरोपों के बीच, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस (ICJ) ने गाज़ा में नरसंहार के 'संभावित जोखिम' के प्रति चेतावनी दी है।

तथ्य	ICJ ने इसके होने पर अंतिम निर्णय दिए बिना नरसंहार के 'संभावित जोखिम' (plausible risk) की चेतावनी दी।
विज्ञान	AI-assisted targeting: बुनियादी ढांचे के विनाश और सामूहिक हत्या के आरोपों में एक कारक के रूप में पहचाना गया।

मेन्स प्रश्न नरसंहार के आरोपों को संबोधित करने में अंतर्राष्ट्रीय न्यायिक निकायों की भूमिका और सक्रिय संघर्ष क्षेत्रों में अंतर्राष्ट्रीय कानून को लागू करने की चुनौतियों का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए।

REGIONAL & GLOBAL GROUPINGS (QUAD, BRICS, SCO, G20...) P

7 सितंबर · NDTV · satyadheesh.in/news/118767

BRICS देशों के बीच जॉइंट स्टेटमेंट पर समझौता होने के करीब

चर्चा में क्यों BRICS वार्ताकार भारत में आयोजित होने वाले शिखर सम्मेलन से पूर्व, विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिकोणों के बावजूद साझा प्राथमिकताओं पर आम सहमति बनाने हेतु एक संयुक्त वक्तव्य को अंतिम रूप दे रहे हैं।

तथ्य	वार्ताकारों ने मतभेदों को कम करने और विवादित बिंदुओं के शब्दांकन पर ध्यान केंद्रित करने हेतु एक शेरपा बैठक आयोजित की। सदस्य देश शुक्रवार को भारत में होने वाले विश्व नेताओं के सम्मेलन से पूर्व मसौदा तैयार करने की समीक्षा और उसे अनुमोदित करने का लक्ष्य रखते हैं।
संस्था	BRICS: राष्ट्रों का एक समूह जो वर्तमान में भारत में आयोजित होने वाले शिखर सम्मेलन के लिए एक संयुक्त वक्तव्य पर बातचीत कर रहा है।

मेन्स प्रश्न बहुध्रुवीय सहयोग के एक मंच के रूप में ब्रिक्स (BRICS) के महत्व और भिन्न अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण रखने वाले राष्ट्रों के बीच आम सहमति प्राप्त करने की चुनौतियों पर चर्चा कीजिए।

INDIA'S BILATERAL RELATIONS P

7 सितंबर · The Hindu · satyadheesh.in/news/118521

पेरिस में स्वामीनारायण मंदिर के उद्घाटन पर नरेंद्र मोदी ने दिया वर्चुअल संबोधन

चर्चा में क्यों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत और फ्रांस के बीच विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी पर प्रकाश डालने हेतु पेरिस में एक स्वामीनारायण मंदिर के उद्घाटन समारोह को आभासी रूप से संबोधित किया।

पद	नरेन्द्र मोदी: भारत के प्रधानमंत्री।
तथ्य	वर्ष 2026 को 'भारत-फ्रांस नवाचार वर्ष' (India-France Year of Innovation) के रूप में नामित किया गया है।
स्थान	फ्रांस के पेरिस में स्वामीनारायण मंदिर का उद्घाटन किया गया।
तथ्य	विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी: भारत-फ्रांस संबंधों का औपचारिक विन्यास।

मेन्स प्रश्न भारत और फ्रांस के बीच विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी को सुदृढ़ करने में सांस्कृतिक कूटनीति और तकनीकी सहयोग किस प्रकार स्तंभों के रूप में कार्य करते हैं, चर्चा कीजिए।

अर्थव्यवस्था

8

MONETARY POLICY, RBI & BANKING

P

7 सितंबर • Economic Times • satyadheesh.in/news/118737

सरकारी सिक्योरिटीज में निवेश आसान, Sebi ने FPIs को दी बड़ी राहत

चर्चा में क्यों SEBI ने एक परिपत्र जारी कर विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (FPIs) को केवल सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश करने की स्थिति में निवेशक समूह का विवरण प्रस्तुत करने से छूट दी है।

- संस्था** भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने जून में सरकारी प्रतिभूतियों में FPI निवेश के लिए एकाग्रता सीमा (concentration limits) को वापस ले लिया।
- तथ्य** यह छूट विशेष रूप से केवल सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश करने वाले FPIs पर लागू होती है।
- तथ्य** डिपॉजिटरीज़ और कस्टोडियनज़ को नए निर्देश के अनुरूप अपने सिस्टम को अपडेट करना आवश्यक है।

मेन्स प्रश्न सरकारी प्रतिभूतियों में विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (FPIs) के लिए निवेश मानदंडों में ढील देने से भारत के राजकोषीय प्रबंधन और पूंजी बाजार की तरलता पर पड़ने वाले प्रभावों की चर्चा कीजिए।

CAPITAL MARKETS & SEBI

P

7 सितंबर • Economic Times • satyadheesh.in/news/118676

ट्रेडिंग वॉल्यूम में भारी गिरावट, सेबी अब डेरिवेटिव्स सेटलमेंट का तरीका बदलेगा

चर्चा में क्यों व्यापार की मात्रा में महत्वपूर्ण गिरावट और बाजार के प्रतिभागियों से प्राप्त प्रतिक्रिया के उपरांत, SEBI ने डेरिवेटिव अनुबंधों के लिए निपटान मूल्य पद्धति (settlement price methodology) की समीक्षा करने की योजना की घोषणा की है।

- तथ्य** NSE का अगस्त टर्नओवर: Rs 34.48 लाख करोड़।
- तथ्य** BSE का अगस्त टर्नओवर: Rs 32.2 लाख करोड़।
- संस्था** SEBI: Securities and Exchange Board of India।
- विज्ञान** क्लोजिंग ऑक्शन सेशन (CAS): डेरिवेटिव सेटलमेंट के लिए एक नया लागू किया गया सत्र।

मेन्स प्रश्न भारत के इक्विटी डेरिवेटिव्स खंड में बाजार की अखंडता और तरलता बनाए रखने में 'सेटलमेंट प्राइस' (निर्णय मूल्य) तंत्र के महत्व का विश्लेषण कीजिए।

CAPITAL MARKETS & SEBI

P

7 सितंबर • Economic Times • satyadheesh.in/news/118672

NSE के IPO से आएंगे 30,000 करोड़ रुपये, IFCI के शेयरों में उछाल

चर्चा में क्यों SEBI ने नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) के IPO के लिए ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट को मंजूरी दे दी है, जिससे लगभग 30,000 करोड़ रुपये जुटाने की उम्मीद है।

- संस्था** SEBI: वह नियामक संस्था जिसने NSE के ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट को मंजूरी दी।
- तथ्य** NSE IPO: 14.89 करोड़ तक के इक्विटी शेयरों की बिक्री के माध्यम से लगभग 30,000 करोड़ रुपये जुटाने की उम्मीद है।
- तथ्य** IFCI-SHCIL-NSE संबंध: IFCI के पास SHCIL की >50% हिस्सेदारी है; SHCIL के पास NSE में >4% की हिस्सेदारी है।
- तथ्य** Grey Market Premium (GMP): नियामक की मंजूरी के बाद प्रति शेयर ₹250-280 तक उछला।

मेन्स प्रश्न भारत में पूंजी बाजार की तरलता को गहरा करने में बड़े पैमाने पर होने वाले प्रारंभिक सार्वजनिक प्रस्तावों (IPOs) के महत्व और कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर उनके प्रभाव का विश्लेषण कीजिए।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पश्चिमी समर्पित माल गलियारा (WDFC) के तीन खंडों को समर्पित करने और ग्लोबल फिनटेक फेस्ट (GFF) 2026 का उद्घाटन करने के लिए गुजरात और महाराष्ट्र के दौरे पर हैं

चर्चा में क्यों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पश्चिमी समर्पित माल गलियारा (WDFC) के तीन खंडों को समर्पित करने और ग्लोबल फिनटेक फेस्ट (GFF) 2026 का उद्घाटन करने के लिए गुजरात और महाराष्ट्र के दौरे पर हैं।

तथ्य	WDFC: माल ढुलाई के लिए समर्पित 326 किमी के तीन खंड।
तथ्य	WDFC: तीनों खंडों के लिए परियोजना लागत 20,700 करोड़ रुपये है।
स्थान	गुजरात और महाराष्ट्र: WDFC खंडों और GFF 2026 की मेजबानी करने वाले राज्य।
विज्ञान	Global Fintech Fest (GFF): उन्नत प्रौद्योगिकियों के माध्यम से वित्त के भविष्य को आकार देने पर केंद्रित सम्मेलन।

मेन्स प्रश्न समर्पित माल गलियारों (डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर) के विकास और फिनटेक पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देना किस प्रकार भारत के वैश्विक विनिर्माण और डिजिटल अर्थव्यवस्था केंद्र बनने के लक्ष्य में योगदान देते हैं, चर्चा कीजिए।

स्मार्ट गैस मीटर लगाने के लिए PNGRB और EESL ने साइन किया MoU

चर्चा में क्यों PNGRB और EESL ने सिटी गैस वितरण क्षेत्र में सुरक्षा और पारदर्शिता बढ़ाने के उद्देश्य से स्मार्ट घरेलू पाइपड नेचुरल गैस (PNG) मीटर तैनात करने हेतु एक समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए हैं।

संस्था	PNGRB: Petroleum & Natural Gas Regulatory Board।
संस्था	EESL: Energy Efficiency Services Limited।
तथ्य	Smart meters में डिजिटल मॉनिटरिंग, टैम्पर अलर्ट, लीकेज डिटेक्शन और रिमोट ऑपरेशंस जैसी विशेषताएँ शामिल होती हैं।
तथ्य	यह पहल City Gas Distribution (CGD) क्षेत्र को लक्षित करती है।

मेन्स प्रश्न भारत के शहर गैस वितरण (CGD) क्षेत्र में स्मार्ट मीटरिंग प्रौद्योगिकियों के एकीकरण से ऊर्जा सुरक्षा और उपभोक्ता सुरक्षा को किस प्रकार सुदृढ़ किया जा सकता है, इसका विश्लेषण कीजिए।

RBI से लिक्विडिटी मैनेज करने के लिए नए टूल्स इस्तेमाल करने की उम्मीद

चर्चा में क्यों बाजार के प्रतिभागियों को यह अपेक्षा है कि RBI, FCNR प्रवाह में अनुमान से अधिक वृद्धि के कारण उत्पन्न ₹5 लाख करोड़ की अतिरिक्त तरलता (excess liquidity) को प्रबंधित करने के लिए 'सेल-बाय डॉलर स्वेप' और 'वैरिएबल रेट रेपो रिवर्सल' (VRRRs) जैसे उपकरणों का उपयोग करेगा।

विज्ञान	VRRR: Variable Rate Repo Reversal, RBI द्वारा तरलता के उतार-चढ़ाव को प्रबंधित करने के लिए उपयोग किया जाने वाला एक उपकरण है।
तथ्य	अतिरिक्त तरलता का प्रबंधन किया जाना है: ₹5 लाख करोड़।
संस्था	OMOs: Open Market Operations में RBI द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों (government securities) की खरीद और बिक्री शामिल होती है।

मेन्स प्रश्न भारतीय अर्थव्यवस्था में तरलता स्थिरता बनाए रखने और पूंजी प्रवाह की अस्थिरता के प्रबंधन में विभिन्न मौद्रिक नीति उपकरणों, जैसे कि 'वैरिएबल रेट रेपो' (VRR) और 'ओपन मार्केट ऑपरेशंस' (OMO) के महत्व का विश्लेषण कीजिए।

विदेशी फंड पर नए नियमों पर AIFs ने SEBI और RBI से की अपील

चर्चा में क्यों अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स (AIFs) ने SEBI, RBI और वित्त मंत्रालय के समक्ष उन मसौदा जुलाई दिशानिर्देशों के विरुद्ध अपील की है, जिनके अंतर्गत बहुसंख्यक विदेशी योगदान वाले AIFs को विदेशी संस्थाओं के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है।

तथ्य	जुलाई के मसौदा दिशा-निर्देशों के तहत, अधिकांश विदेशी योगदान वाले AIFs को विदेशी संस्थाओं के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है।
तथ्य	प्रस्तावित अपवाद: उद्योग जगत ने भारतीय-प्रबंधित फंड्स के लिए FDI प्रतिबंधों से छूट की मांग की है।

मेन्स प्रश्न विदेशी वित्तपोषित निवेश साधनों को विदेशी संस्थाओं के रूप में वर्गीकृत करने के भारत के पूंजी बाजार की तरलता और व्यापार करने की सुगमता पर पड़ने वाले निहितार्थों का विश्लेषण कीजिए।

NSE IPO में जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया समेत 5 कंपनियों के शेयर बिकेंगे

चर्चा में क्यों अपनी सॉल्वेंसी अनुपात (solvency ratios) में सुधार करनेके उद्देश्य से, पाँच सार्वजनिक क्षेत्र की सामान्य बीमा कंपनियाँ (GIC, New India Assurance, National Insurance, United India, और Oriental Insurance) NSE IPO में अपनी हिस्सेदारी का विनिवेश कर रही हैं।

तथ्य	IPO के बाद NSE में पाँच बीमाकर्ताओं की संयुक्त हिस्सेदारी 6.7% से घटकर 5.1% हो जाएगी।
संस्था	NSE (National Stock Exchange) की स्थापना 1994 में हुई थी और यह व्यापार की मात्रा (trading volume) के आधार पर भारत का सबसे बड़ा एक्सचेंज है।
तथ्य	LIC के पास 265.28 मिलियन शेयर हैं, जो NSE के 10.72% का प्रतिनिधित्व करते हैं।
तथ्य	बीमा कंपनियों को SEBI की अनुमति के अधीन NSE के शेयरों में अधिकतम 15% तक हिस्सेदारी रखने की अनुमति है।
तथ्य	मार्च 2025 तक, Oriental Insurance ने -1.03 का solvency ratio दर्ज किया।

मेन्स प्रश्न राज्य के स्वामित्व वाली बीमा कंपनियों के लिए शोधनक्षमता अनुपात (solvency ratios) के महत्व और उनकी वित्तीय सुरक्षा को सुदृढ़ करने में पूंजी बाजार निवेश की भूमिका का विश्लेषण कीजिए।

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी

5

डिफेंस सेक्टर को मिलेगा बूस्ट, DAC ने 1.10 लाख करोड़ के प्रोजेक्ट्स को हरी झंडी दी

चर्चा में क्यों रक्षा अधिग्रहण परिषद (DAC) ने परिचालन क्षमताओं को बढ़ाने और रक्षा विनिर्माण में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देनेके लिए 1.10 लाख करोड़ रुपये के सैन्य खरीद प्रस्तावों को मंजूरी दी है।

संस्था	Defence Acquisition Council (DAC): भारत में सैन्य खरीद को मंजूरी देने वाली सर्वोच्च संस्था।
पद	राजनाथ सिंह: Defence Acquisition Council (DAC) के अध्यक्ष।
तथ्य	खरीद मूल्य: सेना, नौसेना और वायु सेना के लिए Rs 1.10 लाख करोड़ स्वीकृत।
तथ्य	स्वदेशीकरण: स्वीकृत खरीद का लगभग 98% भारतीय उद्योग से प्राप्त किया जाता है।

मेन्स प्रश्न रक्षा क्षेत्र में 'आत्मनिर्भर भारत' के लक्ष्य की प्राप्ति में 'अनिवार्यता की स्वीकृति' (Acceptance of Necessity) के महत्व और रक्षा अधिग्रहण परिषद (DAC) की भूमिका का विश्लेषण कीजिए।

अरावली हिल्स रिपोर्ट के लिए 6 महीने की मोहलत खारिज, 30 नवंबर तक की डेडलाइन

चर्चा में क्यों भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने अरावली पहाड़ियों के निर्धारण पर एक उच्च-स्तरीय समिति की रिपोर्ट के लिए छह महीने के विस्तार को खारिज कर दिया और 30 नवंबर, 2026 की एक निश्चित समय-सीमा निर्धारित की।

पद	सूर्य कांत: सितंबर 2026 तक भारत के मुख्य न्यायाधीश।
स्थान	अरावली पहाड़ियाँ: सीमा का निर्धारण सर्वोच्च न्यायालय द्वारा नियुक्त समिति द्वारा किया जा रहा है।
तथ्य	30 नवंबर, 2026: समिति की अंतिम रिपोर्ट के लिए समय सीमा।
तथ्य	9 फरवरी, 2027: CJI सूर्यकांत की सेवानिवृत्ति तिथि।

मेन्स प्रश्न पर्यावरण संरक्षण में न्यायिक निरीक्षण के महत्व और अरावली पहाड़ियों जैसे संरक्षित क्षेत्रों के लिए पारिस्थितिक सीमाओं को परिभाषित करने में आने वाली चुनौतियों का विश्लेषण कीजिए।

टाइगर वर्म्स से नहीं खत्म होंगे एस्केरिस के अंडे, सेहत के लिए खतरा

चर्चा में क्यों रॉयल सोसाइटी ऑफ केमिस्ट्री के शोधकर्ताओं ने पाया है कि टाइगर वर्म्स (tiger worms) मल अपशिष्ट में एस्केरिस (Ascaris) के अंडों को नष्ट करने में विफल रहते हैं, जिससे वर्मीकंपोस्ट के माध्यम से एस्केरिसिस (ascariasis) के संचरण का जोखिम उत्पन्न होता है।

विज्ञान	टाइगर वर्म्स (Tiger worms): वे जीव जिनका परीक्षण मल अपशिष्ट में Ascaris के अंडों को नष्ट करने की क्षमता के लिए किया जाता है।
तथ्य	Biodigesters में tiger worms के संपर्क में 4 से 14 सप्ताह तक रहने के बाद भी Ascaris के अंडे जीवित (viable) रहे।
पर्यावरण	Ascaris: परजीवी कृमि जिनके अंडे दूषित vermicompost के माध्यम से प्रसारित हो सकते हैं।

मेन्स प्रश्न कृषि में अनुपचारित वर्मीकम्पोस्ट के उपयोग से जुड़े सार्वजनिक स्वास्थ्य जोखिमों की चर्चा कीजिए और जैविक उर्वरकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक उपायों का सुझाव दीजिए।

राजनाथ सिंह करेंगे 40 सुखोई जेट्स का ओवरहाल, पिछले साल के प्लान से दोगुना

चर्चा में क्यों रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा 40 सुखोई-30MKI लड़ाकू विमानों के ओवरहाल के प्रस्ताव पर चर्चा करने के लिए डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल (DAC) की बैठक की अध्यक्षता करेंगे।

पद	राजनाथ सिंह: केंद्रीय रक्षा मंत्री।
तथ्य	Sukhoi-30MKI: Hindustan Aeronautics Limited द्वारा लड़ाकू विमान बेड़े का ओवरहाल किया जा रहा है।
तथ्य	40 जेट विमानों के ओवरहाल प्रस्ताव पिछले वर्ष की योजना से दोगुना है।

मेन्स प्रश्न भारतीय वायुसेना के पुराने होते बेड़े के लिए 'लाइफ एक्सटेंशन' (जीवन विस्तार) रणनीति के महत्व और स्वदेशी रखरखाव सुनिश्चित करने में रक्षा अधिग्रहण परिषद (DAC) की भूमिका का विश्लेषण कीजिए।

ISRO का बड़ा बयान: प्राइवेटाइजेशन नहीं होगा, फोकस R&D और मिशन पर रहेगा

चर्चा में क्यों ISRO ने स्पष्ट किया है कि इसका निजीकरण नहीं किया जाएगा, बल्कि यह उन्नत R&D और रणनीतिक मिशनों पर ध्यान केंद्रित करेगा, जबकि निजी संस्थाएं परिपक्व प्रौद्योगिकियों (mature technologies) का प्रबंधन करेंगी।

संस्था	ISRO: Indian Space Research Organisation।
पद	V Narayanan: ISRO के अध्यक्ष।
पद	पवन गोयंका: IN-SPACe के अध्यक्ष।
तथ्य	लक्ष्य: 2030 तक प्रति वर्ष 50 अंतरिक्ष प्रक्षेपण।

मेन्स प्रश्न भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) की रणनीतिक स्वायत्तता को बनाए रखते हुए भारत के अंतरिक्ष पारिस्थितिकी तंत्र के विस्तार में सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP) की भूमिका का विश्लेषण कीजिए।



टेलीग्राम



वेबसाइट

हर सुबह टेलीग्राम पर पाएँ

रोज़ सुबह 5 बजे पीडीएफ + वीडियो · हर रविवार साप्ताहिक · हिंदी और अंग्रेज़ी · मुफ्त, बिना साइन-अप।

t.me/satyadheesh · satyadheesh.in/upsc/reports

नोट्स सत्याधीश के समाचार फ़ीड से स्वचालित रूप से बनाए जाते हैं और यूपीएससी सीएसई पाठ्यक्रम से जुड़े हैं। उत्तर में उपयोग से पहले तथ्यों का मूल रिपोर्ट या पीआईबी से मिलान करें।